हैदराबाद में 200 करोड़ रूपए के फूड पार्क, सीड एवं फूड प्रोसेसिंग के एमओयू

मुख्यमंत्री भजनलाल ने हैदराबाद में ग्राम-2026 के तहत इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित किया

हैदराबाद/जयपुर, 8 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर एग्रीटेक एवं फूड प्रोसेसिंग के सुनहरे अवसरों की भूमि बन चुका है। कृषि पैदावार में विविधता के कारण राजस्थान में प्रसंस्करण उद्योग, कोल्ड चेन, स्पाइस पार्क एवं कृषि आधारित उद्योगों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इसी दिशा में राज्य सरकार प्रदेश को कृषि आधारित उद्योगों और वैल्यू एडेड

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान प्रदेश को कृषि आधारित उद्योगों और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का वैश्विक केन्द्र बनाने की दिशा में प्रयासरत है।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को हैदराबाद में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 के तहत आयोजित इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित किया।

प्रोडक्ट्स का वैश्विक केन्द्र बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को हैदराबाद में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 के तहत आयोजित इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 'पधारो म्हारो देस' का आ ान करते हुए, निवेशकों, एग्री-टेक स्टार्टअप्स और विशेषज्ञों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद आज देश का प्रमुख आईटी और एग्री इनोवेशन हब बन चुका है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का लैब टू लैंड मॉडल राजस्थान के लिए प्रेरणादायी है और राज्य सरकार इसे और अधिक मजबूती से लागू करना चाहती है।

इन्वेस्टर्स मीट में राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर फूड पार्क, सीड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न एमओयू का आदान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में वन-टू-वन बिजनेस मीटिंग्स एवं निवेशकों, उद्योग जगत और एग्रीटेक विशेषज्ञों के साथ संवाद' किया गया।

इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी मंजू राजपाल, आईसीआरआईएसएटी के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक, फिक्की नेशनल एग्रीकल्चर कमेटी के सह-अध्यक्ष सुब्रतो गीस सहित, कृषि विभाग, राजस्थान फाउंडेशन के हैदराबाद चैप्टर के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स उद्यमी एवं निवेशक उपस्थित थे।

बाइक हाइवे पर खड़े ट्रक में घुसी, पति-पत्नी व तीन बच्चों की मौत

बुलंदशहर, 08 मई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शुक्रवार को एनएच-34 पर हुए एक हादसे में ट्रक से टकरा कर बाइक सवार माता-पिता और तीन बच्चों व सहित, कुल पांच लोगों की मौत हो गयी। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस टीम पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे का शिकार हुआ परिवार वैष्णो देवी धाम के दर्शन कर लौटा था और रिश्तेदार के घर रुकने के बाद आज अपने गांव लौट रहा था।

जानकारी के अनुसार, बुलंदशहर में खुर्जा की तरफ से उत्तम सिंह बाइक से पत्नी और तीन बच्चों के साथ बुलंदशहर नगर के धमेड़ा अड्डा की तरफ अपने घर आ रहे थे। देहात कोतवाली में एनएच-34 पर भंसौली कट के पास बाइक सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही पांचों की मौत हो गई। मृतकों में उत्तम, उनकी पत्नी उर्मिला, बेटा निशांत, बेटी दिशा और मासूम अनायरा शामिल हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

आरपीएससी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द की

सितंबर 2026 में नई परीक्षा होगी, जिसमें केवल वे शामिल होंगे जिन्होंने पिछली परीक्षा दी थी

- **राजस्थान लोक सेवा आयोग 16 मई से पोर्टल पर आवेदन संशोधन की प्रक्रिया शुरु करेगा।**

अजमेर, 8 मई (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार के कड़े रुख और सिफारिश के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। लंबे समय से विवादों और धांधली के आरोपों से घिरी सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 को आयोग ने आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है। प्रदेश के लाखों युवाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए अब यह परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ नए सिरे से आयोजित की जाएगी।

आयोग के अनुसार, नई परीक्षा के सितंबर 2026 में आयोजित होने की प्रबल संभावना है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार कोई नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस री-एग्ज़ाम में केवल 3 लाख 83 हजार 097 अभ्यर्थी ही बैठ सकेंगे। यह मौका सिर्फ उन युवाओं को मिलेगा, जो 13 से 15 सितंबर 2021 के बीच आयोजित हुई लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में भौतिक रूप से उपस्थित हुए थे। यदि किसी अभ्यर्थी ने 2021 में फॉर्म भरा था लेकिन परीक्षा नहीं दी थी, या सिर्फ एक ही पेपर दिया था, तो उसे अब इस नई परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। चूंकि परीक्षा लगभग 5 साल के अंतराल के बाद दोबारा हो रही है, इसलिए आयोग ने अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्रों में आवश्यक सुधार करने का अवसर दिया है।

आगामी 16 मई से पोर्टल पर आवेदन संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी अपने दस्तावेजों, पते या अन्य आवश्यक विवरणों में इस दौरान सुधार कर सकेंगे।

आयोग ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर अपने फॉर्म अपडेट कर लें, ताकि बाद में एडमिट कार्ड जारी करने या चयन प्रक्रिया में कोई तकनीकी अड़चन न आए।

गौरतलब है कि एसआई भर्ती 2021 परीक्षा के आयोजन के बाद से ही इसके पेपर लीक होने व इसमें और डमी कैंडिडेट बिठाने जैसे गंभीर आरोप लगते रहे थे। मामला राज्य सरकार और पुलिस के संज्ञान में आने के बाद कई गिरफ्तारियां भी हुई थीं।

ज्ञातव्य है कि एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने का फैसला दिया था। उसी के तहत राज्य सरकार ने राज्य लोकसेवा आयोग से एसआई भर्ती परीक्षा -2021 रद्द करने की सिफारिश की। इसके बाद आयोग ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है।

नासिक टीसीएस धर्मान्तरण मामले की मुख्य आरोपी निदा खान गिरफ्तार

कोर्ट ने निदा खान को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

- **पता चला है कि छत्रपति संभाजीनगर के नगर सेवक मतीन माजिद पटेल ने निदा खान को शरण दे रखी थी, पटेल को भी आरोपी बनाया गया है।**

नासिक, 08 मई। महाराष्ट्र के नासिक के बहुचर्चित टीसीएस धर्मांतरण मामले में मुख्य संदिग्ध आरोपी निदा खान को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिछले एक महीने से पुलिस को चकमा दे रही निदा खान को नासिक और छत्रपति संभाजीनगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को उसे नासिक रोड न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद, निदा खान फरार हो गई थी। विशेष जांच दल (एसआईटी) को सूचना मिली थी कि वह छत्रपति संभाजीनगर के नारेगांव इलाके में छिपी हुई है। इसके बाद नासिक पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक ने छत्रपति संभाजीनगर के पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार से संपर्क कर संयुक्त अभियान शुरू किया।

जांच में सामने आया कि स्थानीय नगरसेवक मतीन माजिद पटेल ने निदा खान को शरण दी थी। सादे कपड़ों में 20 से अधिक पुलिसकर्मी दो दिनों से इलाके पर नजर बनाए हुए थे। अंततः बिना नंबर वाले वाहनों की मदद से बेहद गोपनीय तरीके से निदा खान को हिरासत में लिया गया।

फरारी के दौरान निदा खान ने नासिक, भिवंडी, मुंब्रा और छत्रपति संभाजीनगर सहित कई स्थानों की यात्रा की। पुलिस के अनुसार, उसने तकनीकी निगरानी से बचने की कोशिश की, लेकिन डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए पुलिस उसके करीब पहुंच गई।

जांच एजेंसियों को उसके मोबाइल फोन से अहम डिजिटल सबूत मिलने की संभावना है। बताया जा रहा है कि मोबाइल में पीड़िता को धर्मांतरण के लिए उकसाने वाले कथित वीडियो और संदेश मौजूद हैं। डेटा रिकवर होने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए नासिक रोड अदालत में सुनवाई 'इन कैमरा' तरीके से की गई। अदालत परिसर के बाहर भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था।

सरकारी पक्ष की ओर से विशेष सरकारी वकील अजय मिसर ने पुलिस हिरासत की मांग की, जबकि बचाव पक्ष के वकील राहुल कासलीवाल और बाबा सैयद ने निदा खान के गर्भवती होने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की। हालांकि अदालत ने यह दलील खारिज करते हुए पुलिस हिरासत मंजूर कर ली। मुख्य आरोपी निदा खान को शरण देने वाले नगरसेवक मतीन पटेल को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक ने कहा, जांच में बाधा डालने या आरोपियों की मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

रेजिडेंसियल स्कूल में निर्माण के लिये 800 साल पुराना मंदिर तोड़ा

- **राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण में शिकायत के बाद संस्कृति मंत्रालय व पुरातत्व विभाग ने मामला दर्ज किया।**

हैदराबाद, 08 मई। तेलंगाना के वारंगल जिले में एक यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल के निर्माण के लिए 800 साल पुराने काकतीय कालीन शिव मंदिर को बुलडोजर से ढहा दिया गया, जिससे आक्रोश और कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। खानपुर मंडल के अशोक नगर में हुई इस घटना पर राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएचए) में शिकायत के बाद केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय और पुरातत्व विभाग ने मामला दर्ज कर लिया है।

वकील इम्मनेनी रामा राव ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि काकतीय शासक गणपति देव (1199-1262 ईस्वी) के शासनकाल के इस शिव मंदिर को खानापुर मंडल में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल के निर्माण के लिए भारी मशीनों से नष्ट कर दिया गया। शिकायत में कहा गया कि अधिकारियों ने तेलंगाना हेरिटेज एक्ट के तहत अनिवार्य विरासत संरक्षण समिति का गठन नहीं किया। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि मंदिर को ध्वस्त करने के बजाय उसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता था।

रिपोर्टों के अनुसार मंदिर के गर्भगृह को खोदा गया था, जिससे यह संदेह पैदा हो गया है कि ठेकेदार ने नीचे दबे कथित खजाने की तलाश में इसे नष्ट किया होगा। हालांकि जिला प्रशासन ने इन आरोपों का खंडन किया। वारंगल जिला कलेक्टर कार्यालय के अनुसार छह मई को किए गए संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि जमीन पर भारी झाड़ियां और पेड़ उगे हुए थे।

बिहार में बिजली गिरने से 7 की मौत

पटना, 08 मई। बिहार के विभिन्न जिलों में शुक्रवार देर शाम आये आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से सात लोगों की मौत हो गई।

राज्य में आकाशीय बिजली गिरने से भोजपुर में 01, पटना में 01, समस्तीपुर में 01 और पूर्वी चंपारण में 01 तथा आंधी-तूफान/तेज वर्षा से पेड़ गिरने के कारण दबकर पटना में 02 एवं वैशाली में 01 व्यक्ति की मृत्यु पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है।

'अनिल अंबानी की कंपनियों के बैंकिंग फ्रॉड की गहन जांच हो'

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की

- **सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक जांच एजेंसी अनिल अंबानी की गिरफ्तारी की मांग नहीं करती वह इसका आदेश नहीं दे पाएगी।**

नई दिल्ली, 08 मई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बड़े पैमाने पर बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले में एक गहन जांच की जरूरत है। यह मामला तब सामने आया, जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बताया कि सात मामलों में अनुमानित कुल नुकसान लगभग 27,337 करोड़ रुपये है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ, पूर्व नौकरशाह ई.ए.एस. शर्मा द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली एडीएजी फर्मों द्वारा 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित ऋण धोखाधड़ी में अदालत की निगरानी वाली जांच की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों ने इसे 27,000 करोड़ रुपये का घोटाला बताया है। अनिल अंबानी को इसका किंगपिन कहा है, लेकिन अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है।

पीठ ने इस बात पर गौर किया कि शीर्ष अदालत ने बार-बार कहा है कि जब तक जांच एजेंसी की ओर से गिरफ्तारी की मांग नहीं की जाएगी, वह इसका निर्देश देने में संकोच करेगी। पीठ ने कहा कि जांच को सनसनीखेज बनाने के बजाय, ध्यान जांच और प्रासंगिक सामग्री के संग्रह पर होना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि किसी मामले में हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता जांच एजेंसी के विवेक पर छोड़ दी जानी चाहिए।

जांच एजेंसियों की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के खिलाफ एसबीआई द्वारा दर्ज शिकायतों पर दो प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। उन्होंने कहा, "कुल नौ प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जिनमें से सात जांच के अधीन हैं और दो में आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं। सात मामलों में, कुल 27,337 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।"

मेहता ने बताया कि त्वरित जांच के लिए कई जांच अधिकारियों की कई टीमें बनाई गई थीं, और जिन सात मामलों में जांच चल रही थी, उनमें 14 स्थानों पर तलाशी ली गई थी। उन्होंने कहा कि 31 लुक-आउट सर्कुलर जारी किए गए हैं और इन मामलों में लगभग 3,960 दस्तावेज एकत्र किए गए हैं। मेहता ने यह भी बताया कि इन मामलों में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और उन्होंने इन सात मामलों में आरोप पत्र दायर करने के लिए एक अस्थायी समय-सीमा भी दी।

अनिल अंबानी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि जब संबंधित अदालत ने अभी तक आरोप पत्र पर संज्ञान नहीं लिया है, तो याचिकाकर्ता को एक आरोप पत्र की प्रति कैसे मिल सकती है।

आकाशवाणी ने 90 वर्ष पूरा होने पर मैराथन आयोजित किया

नई दिल्ली, 08 मई। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में शुक्रवार को यहां आकाशवाणी मुख्यालय से मैराथन का आयोजन किया गया। इसको प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) गौरव द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय प्रसारक के साथ एकजुटता दिखाते हुए फिट इंडिया की भावना को बढ़ावा देना था। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी ये मैराथन आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन तथा आरबीआई भवन से होते हुए वापस आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। इस आयोजन में आकाशवाणी के कर्मचारियों के साथ-साथ भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) जैसे अर्धसैनिक बलों के जवानों ने भी दौड़ लगाकर फिट इंडिया की भावना को प्रदर्शित किया।

अजीबो-गरीब तर्क ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन के प्रति भारी और व्यापक समर्थन है, जिन्होंने पिछले पांच सालों में लेफ्ट फ्रंट सरकार के खिलाफ संघर्ष का लगातार नेतृत्व किया।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "सतीशन के लिए पूर्ण समर्थन है, और अगर नेतृत्व के.सी. वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाता है, तो इतनी बड़ी फूट और मजबूत मतभेदों के बीच वे पार्टी, सरकार और राज्य नहीं चला पाएंगे।"

सभी प्रमुख हितधारकों, जिनमें वी.डी. सतीशन, रमेश चेन्नीथला, वेणुगोपाल और अन्य शामिल हैं, को दिल्ली बुलाया गया है और कल एक बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि इस मुद्दे पर चर्चा हो और पूरी प्रक्रिया में समझदारी लाई जा सके।

वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पिछले 9 वर्षों से वे संगठन के प्रभारी एआईसीसी महासचिव रहे हैं और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं।

जो लोग वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि आने वाले साल में उत्तर प्रदेश चुनाव और 2029 के आम चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए पार्टी को संगठन प्रभारी के रुप में हिंदी भाषी क्षेत्र के हिंदी बोलने वाले व्यक्ति की जरूरत है, ताकि यह साबित किया जा सके कि संगठन को कुर्सी पर नया नेतृत्व चाहिए और केरल को के.सी. वेणुगोपाल की जरुरत है।

सियासी खींचतान जारी है और पार्टी का केरल संगठन और एआईसीसी इस मुद्दे पर पूरी तरह विभाजित हैं।

पार्टी की एकता बिखरी हुई है और आज केरल कांग्रेस गंभीर रूप से विभाजित है।

अरुणाचल प्रदेश में भूकंप

इटानगर, 08 मई। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिला में शुक्रवार को दोपहर बाद मध्यम तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किये गये। भूकंप के चलते कहीं से किसी भी तरह के

- **किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं।**

नुकसान की खबर नहीं है।

भारतीय सिस्मोलॉजी केन्द्र के अनुसार, अरुणाचल में 04 बजकर 05 मिनट 52 सेकेंड पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई।

भूकंप का केन्द्र पापुम पारे जिला में जमीन के अंदर 05 किलोमीटर नीचे स्थित था। भूकंप का एपीक सेंटर 27.390 उत्तरी अक्षांश तथा 93.853 पूर्वी देशांत्तर पर स्थित था।

'हमारे 300 से अधिक कार्यकर्ता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिए आयोग स्थापित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

ममता बनर्जी की पिछली सरकार के कुछ कार्यों की जांच के लिए भी एक आयोग स्थापित किया जा रहा है।

पूरी तरह से जांच शुरू हो गई है और शुभेन्दु अधिकारी के व्यक्तिगत सहायक के हत्यारों की तलाश शुरू हो गई है, जिनकी हत्या एक दिन पहले राजनीतिक कारणों से की गई थी।

नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों द्वारा कल कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कम से कम बीस भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में शपथ ली जाएगी।

दुर्भाग्यवश, अपनी असभ्यता जारी रखते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समारोह में भाग नहीं लेंगी। इससे पहले सभी सेवानिवृत्त मुख्यमंत्री अगले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते रहे हैं।

वैसे, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, ममता बनर्जी "पूर्व" शब्द जोड़ने क बजाय अब भी खुद को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं।

शुभेन्दु को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करने की घोषणा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम कोलकाता में की, जब नव निर्वाचित विधायकों का एक सम्मेलन संपन्न हुआ। भाजपा संसदीय बोर्ड ने अमित शाह को विधायकों की बैठकों की अध्यक्षता करने और नेता व मुख्यमंत्री चुनने का कार्य सौंपा था।

गृह मंत्री ने सदन के नेता और मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित नाम आमंत्रित किया था, जिस पर नव निर्वाचित विधायकों ने एकमत होकर शुभेन्दु अधिकारी का नाम ज़ोर से पुकारा। जब अमित शाह ने मुख्यमंत्री पद के नाम की घोषणा की, तब विधायकों ने कोई अन्य वैकल्पिक नाम नहीं दिया।

लेकिन शुभेन्दु की इस शानदार जीत पर एक दुख की छाया भी थी, क्योंकि उनके युवा कार्यकारी सहायक, जो भारतीय वायुसेना के पूर्व कर्मचारी थे, की एक दिन पहले राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। भावुक अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से शोक व्यक्त किया कि उनके पी.ए. को भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र (ममता बनर्जी के गढ़) में उनकी जीत का मूल्य चुकाना पड़ा।

मौजूदा हालात में कोई और विकल्प अकल्पनीय होता। अधिकारी ने 2021 से लगातार सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी थी।

इस मोड़ पर शुभेन्दु को छोड़कर किसी अन्य उम्मीदवार को चुनने से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष और निराशा पैदा होती, जो बंगाल में पार्टी के पहले कदम को ही बाधित कर सकता था। पार्टी कार्यकर्ताओं को सत्ताधारी दल द्वारा लगातार और बेरहम तरीके से प्रताड़ित किया गया। भाजपा का दावा है कि पार्टी के कम से कम 300 ग्राउंड-लेवल कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया और मारा गया, जबकि कई अन्य को प्रताड़ना और हत्या से बचने के लिए अपने घर छोड़ने पड़े।

शुभेन्दु ने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा और जहां भी पार्टी संकट में थी, वे स्वयं वहाँ पहुंचे। शुभेन्दु स्वयं हमेशा खतरे में रहे।

पार्टी अब नई शुरुआत और राज्य के लोगों की उम्मीदों की दहलीज़ पर है।

विजय आज शपथ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करने की सहमति दी।

शुक्रवार को चेन्नई में बातचीत हुई, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने व्यक्तिगत रूप से वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन से बात कर टीवीके नेतृत्व वाले गठबंधन के समर्थन को सुनिश्चित किया।

इसके तुरंत बाद, सीपीआई कार्य समिति और सीपीएम की राज्य नेतृत्व टीम ने भी विजय का समर्थन किया, जिससे अगले सरकार बनाने को लेकर अनिश्चितता समाप्त होने की संभावना बढ़ गई।

राज्यपाल और विजय ने बुधवार और गुरुवार को भी मुलाकात की थी। दोनों बार अरलेकर ने विजय के सरकार बनाने के दावे को खारिज कर दिया, यह तर्क देते हुए कि टीवीके नेता के पास विधानसभा में आवश्यक समर्थन नहीं है।

लोक भवन ने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि "सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन" स्थापित नहीं हुआ है।

इस निर्णय के बाद टीवीके कार्यकर्ताओं ने राज भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि कांग्रेस ने राज्यभर में राज्यपाल और केन्द्र की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की घोषणा की।

गुरुवार को अरलेकर के निर्णय के जवाब में, कांग्रेस नेता गिरीश चौडणकर ने कहा कि राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना ही चाहिए। उन्होंने मीडिया से कहा कि बहुमत का परीक्षण केवल विधानसभा के पटल पर किया जा सकता है।

उन्होंने भाजपा एवं आरएसएस पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया, जबकि भाजपा के पास विधानसभा में केवल एक विधायक है।

तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष के. सेल्वापेरुंथगई ने 8 मई को सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की अपील की, आरोप लगाते हुए कि राज्यपाल संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और टीवीके को सरकार बनाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

बाद में, विजय ने सीपीआई राज्य मुख्यालय का दौरा कर नेताओं को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्कूल जाते समय मुख्यमंत्री से एक बार फिर मिलीं और अपनी मांग दोहराई, तो मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए बताया कि जाजोद के स्कूल में विज्ञान संकाय शुरू हो चुका है। राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब इस विद्यालय में आप गणित एवं जीव विज्ञान दोनों में से अपनी रुचि अनुसार विषय चुनकर इसी साल से पढ़ाई कर सकती हैं। मुख्यमंत्री के मुंह से खुशखबरी सुनकर बच्चियों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। उनका कहना था कि उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा कि उनकी मांग इतनी जल्दी पूरी होगी।

ममता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजनीतिक संदेश भी माना जा सकता है। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

टीवीके के सभी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पार्टी कोर्ट जाने की योजना बना रही है।

द्रमुक ने शुक्रवार को एक बैठक की, जिसमें चार प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें से एक प्रस्ताव पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन को "आपातकालीन निर्णय लेने" का अधिकार देता है। प्रस्ताव के बारे में द्रमुक ने कहा, "हमारा मुख्य उद्देश्य है कि एक और चुनाव को टाला जाए, एक स्थिर सरकार बनाई जाए और साम्प्रदायिक ताकतों को कोई मौका न दिया जाए।"

बहुमत की कमी को "जटिल संकट" बताते हुए, द्रमुक ने अपने सभी विधायकों से कहा है कि वे 10 मई तक चेन्नई में रहें।

हालांकि, द्रमुक के शीर्ष सूत्रों ने पुष्टि की कि एक योजना पर विचार किया जा रहा है, जिसमें ई. पलानीस्वामी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और द्रमुक बाहर से समर्थन देगा।

द्रमुक के कुछ युवा नेताओं, विशेषकर उदयनिधि स्टालिन के शिविर को डर है कि विजय सत्ता में आने के बाद एम.जी. रामचंद्रन की तरह हो जाएंगे और उन्हें हटाना लगभग असंभव होगा। विख्यात एमजीआर ने जीवन भर द्रमुक को सत्ता से बाहर रखा था।

पार्टी के पुराने नेता, जिनमें एमके स्टालिन शामिल हैं, अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। सूत्रों के अनुसार, वे इस प्रयोग पर जनता की प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि यह दो पार्टियों का साझा प्रयास है, जो दशकों से आमने-सामने रही हैं, और उन्हें भारी विरोध का डर है।

अन्नाद्रमुक ने भी इसी तरह का कदम उठाया है, जिसने अपने विधायकों से कहा है कि वे प्रतीक्षा करें और देखें। पार्टी के एक हिस्से को टीवीके के साथ गठबंधन की जल्दी है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है।

टीवीके ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खराब है, जिसने 23 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को हराया। अय्यर ने कहा, कांग्रेस ने पांच सीटें जीतीं, उसने ये सीटें अपने दम पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से द्रमुक के साथ अपनी दशकों पुरानी कनिष्ठ साझेदारी के बल पर जीतीं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908